



મરદા દૃક્

पादिक

**विज्ञापन एवं
वार्षिक सदस्यता
हेतु कार्यकारी
सम्पादक -
सहर
मो. 8107416712**

वर्ष 06 अंक 3 कुल पृष्ठ 4

अजमेर, गुरुवार, 16 मई 2024

Email ID : marudharatoday.info@gmail.com

मूल्य : 3/- रुपये

पीएम मोदी ने वाराणसी से भरा पर्चा, सम्पत्ति के नाम पर सिर्फ 3.02 करोड़ रुपए, खुद के नाम न चल न अचल सम्पत्ति



वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। पुष्ट नक्षत्र में उन्होंने मुख्य निवार्चन अधिकारी का कार्यालय में पर्चा दाखिला किया। प्रधानमंत्री के नामांकन में चार प्रस्तावक शामिल रहे। इसमें गणेश्वर शास्त्री द्वितीय, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा व दलित समाज के संजय सोनकर शामिल थे। गणेश्वर शास्त्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था, जबकि बैजनाथ पटेल जनसंघ के समय के कार्यकर्ता हैं। इससे पहले गंगा सप्तमी पर मां गंगा को नमन करने

के उपरांत प्रधानमंत्री काशी कोतवाल काल भैरव के दर पर पहुंचे, वहां उनसे अनुमति लेकर नामांकन किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य के बैंकट रमन घनपाठी ने गंगा पूजन कराया। गंगा पूजन कराने वालों में तीन पुजारी तमिलनाडु व एक-एक पुजारी आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र के रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद कूज पर दशाश्वमेध घाट से गंगा विहार करते हुए आदिकेशव घाट तक गए, फिर नमो घाट उतरे। लगातार दो बार प्रधानमंत्री रहने और पिछले 10 साल में देश के चार करोड़ गरीबों को घर

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सभी विविध में पूरी तरह से लागू किया जाएगा



जयपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सभी विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से लागू किया जाए। मिश्र मंगलवार को राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में रोजगारोनुसुखी कौशल विकास समावेशी कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। प्रदेश में स्थानीय उद्योगों एवं विश्वविद्यालय सहभागिता से रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों में शोध एवं अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करने पर भी जोर दिया। बैठक में विश्वविद्यालय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार कलसचिव और वित्त नियंत्रक के पदों पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर उन्हें भरे जाने, इन पदों पर लगने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के आकर्षण के लिए अतिरिक्त भर्ते के प्रावधान, प्रोत्साहन आदि पर भी चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि इन पदों पर ऐसे अधिकारी लगाए

जाएं जो विश्वविद्यालय के हित में प्रभावी सेवाएं दें। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान के विश्वविद्यालय भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनाने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने विश्वविद्यालयी शिक्षा के जरिए युवाओं को देश के विकसित भविष्य के लिए कार्य करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बैठक में जिन विश्वविद्यालयों में सौर ऊर्जा उपकरण नहीं लगे हैं, वहां 30 जून तक कार्रवाई किए जाने के भी राज्यपाल ने निर्देश दिए।

बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, विश्वविद्यालयों के कुलपति, मुख्य सचिव सुधांश पंत, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, सामाजिक न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों ने भाग लिया।

24 हजार छोटी खानों में जल्द शुरू होगा खनन

जयपुर। राजस्थान में जल्द ही 24 हजार छोटी खानों में खनन का काम शुरू हो सकेगा। प्रदेश में पांच हैक्टेयर से छोटी इन खानों की लीज व कवारी लाइसेंस के बाद इन खान मालिकों ने जिला स्तर की पर्यावरण स्वीकृतियां यानी ईसी पहले ही प्राप्त कर ली हैं। अब इनको नियमानुसार राज्यस्तरीय कमेटी से ईसी जारी होनी है। जानकारी के अनुसार इनमें से जिला स्तर पर 12 हजार खानों को ईसी मिलने के बाद इनकी राज्यस्तरीय ईसी के लिए स्कूटनी का काम भी पूरा हो गया है। वहीं शेष 12 हजार की जल्द स्कूटनी पूरी हो जाएगी। विभाग ने सभी खानों के दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने इसे लेकर खान, पर्यावरण विभाग व राज्य स्तरीय एनवायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट एथारिटी यानी सीया से तय समय सीमा में ईसी जारी करने के निर्देश समीक्षा बैठक में दिए हैं। एनजीटी ने ऐसी खानों को एक साल में जिला स्तरीय कमेटियों से ईसी मंजूरी के बाद सीया से मंजूरी देने का राइडर तय कर रखा है। ऐसे में इस समयावधि में सभी खानों को ईसी देने को सीया को पाबंद किया गया है ताकि इनमें खनन शुरू हो सके। उन्होंने लाइसेंसधारकों व खान मालिकों से शेष औपचारिकताएं खान विभाग द्वारा जल्द पूरी कराने, छोटी-मोटी कमियों को पूरा करने के लिए अनावश्यक पत्राचार ना करने सीधे लाइसेंसधारकों से संपर्क करने को कहा है ताकि विलंब ना हो।

देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं सीएए लागू होगा : मोदी



बैरकपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दोहराया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देगा क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया समूह मुस्लिम समुदाय के लिए प्रयास कर रहा है। मोदी ने बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए एसटी और एससी के लिए मौजूदा आरक्षण में कटौती से इनकार कर दिया। उन्होंने नागरिकता संशोधन (सीएए) को लागू करने के लिए प्रतिज्ञा व्यक्त की, जो उन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए है जो दुनिया के अन्य हिस्सों से धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किए जाने के बाद भारत आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संदेशखाली की बहनों को डराया-धमकाया जा रहा है। कांग्रेस को इस बार उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी। राहुल गांधी इस साल 19 जून को 54 साल के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संदेशखाली में यौन उत्पीड़न के मामले में कथित वीडियो पर कहा कि पहले टीएमसी नेताओं को पुलिस ने बचाया। अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेशखाली की बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सिर्फ़इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उन्होंने कहा, बंगाल में टीएमसी की सरकार में राम का नाम नहीं लेने दिया जाता। रामनवमी नहीं मनाने दी जाती।

क्राउड फंडिंग के जरिए 23 महीने के हृदयांश को जेकेलोन अस्पताल में लगा 17.50 करोड़ का जीवनदायिनी इंजेक्शन



था लेकिन छह महीने बाद जब परिवार के लोगों ने किसी सहारे से खड़ा करने की कोशिश की तो वह खड़ा नहीं हो पाया था। इसके बाद बीमारी का पता चला था। डॉ. माथुर ने बताया कि अमेरिकन दवा कंपनी नोवार्टिस द्वारा बनाया गया जोलगेनेस्मा इंजेक्शन फिलहाल एसएमए की बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे कारगर और महंगा इंजेक्शन है। इसकी कीमत 17.50 करोड़ रुपए है। यह इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली जीन थेरेपी है। इसके जरिए जीन पूरे शरीर में पाए जाने वाले एसएमएन प्रोटीन को एनकोड करता है, जो मोटर न्यूरॉन्स के रखरखाव और कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि इसी बीमारी से पीड़ित बच्चे की मदद के लिए कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने गत वर्ष पीएम मोदी को पत्र लिखा था। डॉ. प्रियांशु ने बताया कि इस बीमारी के कारण मसल्स में कमजोरी आने लगती है। बच्चे को चलने-फिरने में परेशानी होती है। सांस रुकने की भी संभावना रहती है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक दुर्लभ बीमारी है जो रीढ़ की हड्डी में मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है।

ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित

जयपुर। एसएमएस में फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने एसआईटी गठन करने के आदेश दिए थे। इस पर जयपुर कमिशनर बीजू जॉर्ज जोसफ ने एसआईटी का गठन कर दिया है। ऐसे में अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में दर्ज तीनों एफआईआर की जांच अब एसआईटी करेगी। इस एसआईटी में आठ पुलिस अधिकारी और कॉन्स्टेबल शामिल हैं। इस एसआईटी की ओर से की जा रही जांच की मॉनिटरिंग जयपुर पुलिस कमिशनर बीजू जॉर्ज जोसफ करेगे। पुलिस कमिशनर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में हर दिन एक नई जानकारी टीम को मिल रही है। उन सभी पर टीम काम कर रही हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन कर दिया गया है।

ट्रैफिक पुलिस हुई सक्रिय, चलाया विशेष अभियान 150 से ज्यादा वाहनों के बनाए चालान



अजमेर। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए यातायात पुलिस ने सोमवार को विशेष कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन से पड़ाव तक अभियान चलाया। इसमें बैतरीबी खड़े 150 वाहनों के चालान बनाए और 45 से अधिक वाहनों को जब्त किया। रेलवे स्टेशन के सामने नगरीय वाहनों के जमावड़ से यातायात में व्यवधान होने की शिकायतों के बाद यातायात पुलिस सक्रिय हुई। यातायात निरीक्षक भीकाराम काला के नेतृत्व में पुलिस जापे ने रेलवे स्टेशन के दूसरे नम्बर गेट से अस्थाई

अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कई टैमों सड़क पर खड़े हुए मिले। पुलिस को देखते हुए टैमों चालक अपने वाहन लेकर खिसक लिए। जो पुलिस के हत्ये चढ़े उनके चालान बनाए गए। इसके बाद सड़क पर खड़े दोषिया वाहनों को जब्त किया गया। रेलवे स्टेशन के सामने नगरीय वाहनों के जमावड़ से यातायात में व्यवधान होने की शिकायतों के बाद यातायात पुलिस ने दुकानदारों को अपना सामान दुकानों की सीमा में रखने के लिए पाबंद किया। यातायात पुलिस ने शिवाजी पार्क, पड़ाव और कर्वंडसपुरा क्षेत्र में सड़क पर खड़े रहने वाले ठेले चालकों को चेतावनी दी है कि ये समझाइश का अन्तिम अवसर है। यदि इसके बाद भी सड़क पर ठेले खड़े पाए गए तो ठेलों को सीज करने के साथ ही पुलिस में मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। साथ ही सीज किए गए सामान को रिलीज नहीं किया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की फूड सेप्टी टीम ने की कार्रवाई, दूषित तेल में तला गया सामान व पानी की बोतलें की जब्त



अजमेर। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की फूड सेप्टी टीम ने मंगलवार को केन्द्रीय रोडवेज बस स्टैण्ड स्थित ढाबों और फूड स्टॉलों का निरीक्षण किया। यहां पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के 102 कर्टन कुल 1224 बोतलें जब्त की, जिन पर पैकिंग दिनांक, बैच नम्बर आदि सूचनाएं अंकित नहीं थीं। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ज्योतिसना रंगा के अनुसार पिछले दिनों शिकायत मिली थी कि बस स्टैण्ड पर पानी और कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सप्रायर बोतलें बेची जा रही हैं। इस पर टीम को केन्द्रीय रोडवेज बस स्टैण्ड भेजा गया। जहां पांच दुकानों का सघन निरीक्षण करने पर वहां बेची जा रही एक्वा ब्रांड पानी की बोतलों पर खाद्य सुक्ष्म तथा मानक अधिनियम के नियमानुसार अनिवार्य पैकिंग दिनांक, बैच नम्बर आदि

सूचनाएं अंकित नहीं पाई गईं। मैसर्स फरीद जनरल स्टोर पर सबसे ज्यादा 70 कर्टन मिले। इसके मालिक फरीद से पूछताछ करने पर बताया कि नागौर की एक कम्पनी वहां से पिकअप भरकर सप्लाई के लिए यहां भेजती है। एक कर्टन की कीमत रुपए 66 है जिसमें 12 बोतल होती हैं। एक बोतल 20 रुपए में बेचते हैं। फरीद ने सप्लायर से मोबाइल नम्बर पर बात करवाई। जिसे थांवला, नागौर से बुलवाकर इस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की सैम्प्लिंग की गई। मौके पर नियमों का उल्लंघन होने पर पैकिंग दिनांक अंकित नहीं होने से नमूना लेने के बाद सभी बोतलों के पानी को नष्ट किया गया। सप्लायर पंकज कुमार ने अपना पक्ष खरें हुए बताया कि प्रिंटिंग मशीन खराब होने से पैकिंग दिनांक, बैच नम्बर आदि बिना प्रिंट किए बोतलें सप्लाई

वन विभाग करेगा 23 मई को वन्य जीवों की गणना



अजमेर। वन विभाग ने जिले के जंगलों में 23 व 24 मई की वाटर होल्स पद्धति से होने वाली वन्य जीव गणना के लिए वाटर होल्स चिह्नित कर लिए हैं। इस बार मंडल की छह रेंज के जंगलों में कुल 63 वाटर होल्स पर वन्य जीव गणना होगी। जो कि पूर्व के सालों के मुकाबले कम है। पूर्व में 80 से अधिक वाहर होल्स पर गणना होती थी। इधर विभाग ने गणना दलों में शामिल कार्मिकों को प्रशिक्षण भी दिया है। साथ ही उन्हें जीवों की पहचान के लिए रेंजिंग फोटो मय विवरण पुस्तिका भी बांटी गई है। जिससे कि सटीक गणना हो सके। उप वन संरक्षक सुगानाराम जाट ने बताया कि गणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन वाटर होल्स को चिह्नित किया गया है, जिनमें वर्तमान में पानी है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मंडल को

प्यास बुझाने के लिए आते हैं। कुछ ऐसे भी वाटर होल्स हैं, जहां वन्य जीव आते हैं लेकिन वर्तमान में ये सूखे हैं। इसीलिए रेंजस को ऐसे वाटर होल्स को पानी से भरने के लिए एक लाख रुपए का बजट उपलब्ध कराया गया है। कुल 63 वाटर होल्स पर 23 मई को सुबह वन्य जीव गुणना शुरू होगी, जो अगले दिन सुबह 8 बजे तक चलेगी। गणना के लिए 63 ही दल बनाए गए हैं। प्रत्येक दल में दो-दो वनकार्पिक शामिल होंगे। गणना में वॉलटिंग का भी सहयोग लिया जाएगा। अजमेर वन मंडल की नसीराबाद रेंज के जंगलों में सबसे ज्यादा 16 वाटर होल्स बनाए गए हैं। जबकि किशनगढ़ में 14, अजमेर में 13, व्यावर में 8 तथा पुष्कर व सरवाड़ में 6-6 वाटर होल्स पर वन्य जीव गणना होगी। ऐसे वाटर होल्स जहां पर अधिक संख्या में विभिन्न प्रजाति के वन्य जीवों के आने की संभावना है, वहां पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। ऐसे वाटर होल्स जहां पर अधिक संख्या में विभिन्न प्रजाति के वन्य जीवों के आने की संभावना है, वहां पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। एक्सील और स्पोकिंग पर भी प्रतिबंध होगा। साथ ही मचान पर बैठते समय जूने भी वहां रखें होंगे। गणना के समय कोई कार्मिक अपने साथ कोई भी सुर्गंधित वस्तुएं नहीं ले जा सकेंगे। कपड़ों पर परफ्यूम या सिर में सुर्गंधित तेल भी नहीं लगा होना चाहिए। एल्कोहल और स्पोकिंग पर भी प्रतिबंध होगा। साथ ही मचान पर बैठते समय जूने भी वहां रखें होंगे। गणना के समय कोई कर्मचारी ना सोएगा और ना ही बात करेगा। उल्लेखनीय है कि वन्य जीव गणना के माध्यम से वन मुख्यालय क्षेत्रवार हुए बदलाव के आंकड़े तैयार करेगा।

बिना छुट्टी 77 चिकित्साकर्मी गायब, अब नौकरी पर संकट के बादल

जयपुर। राजस्थान के चिकित्सा विभाग में लंबे समय से बिना छुट्टी मंजूर किए और मनमजी ड्यूटी से गायब हुए चिकित्साकर्मियों पर कर्वाई की तैयारी है। अभी प्रदेशभर में ऐसे 77 चिकित्साकर्मी हैं, जो लंबे समय से बिना किसी सूचना के विभाग की तय ड्यूटी से लापता हैं। इन सभी को नोटिस जारी होंगे, अगर तीन दिन में अनुपस्थित रहने का संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इनकी नौकरी पर संकट के बादल मंडराएंगे। इन पर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है। जानकारी के अनुसार इन 77 चिकित्साकर्मियों के अलावा भी विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्रशासन, जोनों के संयुक्त निदेशकों, सीएमएचओ, पीएमओ सहित अन्य नियंत्रण अधिकारियों को पत्र लिखकर और भी ऐसे चिकित्साकर्मी होंगे तो उनकी सूचना मांगी है। चिकित्सा विभाग की एसीएस शुभ्रा सिंह ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए इनके खिलाफ तय नियमों के अनुसार कर्वाई के आदेश दिए हैं। विभाग के अतिरिक्त निदेशक रकेश कुमार शर्मा ने बताया कि ऐसे कार्मिकों को 3 दिन में ड्यूटी पर उपस्थित होने के नोटिस जारी किए जाएंगे। अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के परिवेशकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करने, वित्त विभाग के आदेश तथा राजस्थान सिविल सेवा नियम 86 के तहत कर्वाई की जाएंगी। इसके लिए नियंत्रण अधिकारी 15 दिवस में प्रस्ताव भिजवाएंगे।

विश्वविद्यालयों में 30 मई तक लाग होगा बायोमेट्रिक-मोबाइल एप से हाजरी सिरस्टम

जयपुर। प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में 30 मई तक बायोमेट्रिक और मोबाइल एप से उपस्थिति की व्यवस्था लागू होगी। इस संबंध में राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को यहां राजभवन में हुई बैठक में सभी कुलपतियों को निर्देश दे दिए। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक-मोबाइल एप आधारित उपस्थिति की व्यवस्था 30 मई तक सभी विश्वविद्यालयों में तत्परता से लागू की जाएगी। चरणबद्ध रूप से यह व्यवस्था विश्वविद्यालयों के सभी महाविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में भी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि नवगठित विश्वविद्यालयों में संपत्तियों, दायित्वों, भूमि, पैसन तथा अन्य मुद्दों के लिए कमेटी का गठन कर कार्य किया जाएगा। इसमें संबंधित जिला कलेक्टर भी सम्मिलित होंगे ताकि नए विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दों का प्रभावी समाधान समय पर हो सके। उन्होंने कहा कि सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अब प्रत्येक विश्वविद्यालय पांच-पांच ग्राम गोद लेकर उनके विकास के लिए कार्य करेंगे। मिश्र ने सभी कुलपतियों से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक रिक्त पदों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने रिक्त पदों को भरे जाने के लिए भी चरणबद्ध प्रभावी कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया।

यादगार अंजुमन चुनाव नई मतदाता सूची जारी

अजमेर। स्वाजा मोनुदान हसन चिशी की दरगाह की यादगार अंजुमन की 11 सदस्यीय कार्यकारियों के चुनाव के लिए 245 मतदाताओं की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इसके साथ ही अब चुनावी मैदान में उत्तरने वालों की सक्रियता बढ़ गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 16 मई तय की गई है। अंजुमन यादगार के सदर

मरुधरा टुडे

कांग्रेस की दिशाहीनता एवं बढ़ता पलायन

आज के परिदृश्यों में कांग्रेस अनेकों विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरी है। चुनाव प्रचार हो या उम्मीदवारों का चयन, राजनीतिक वायदे हो या चुनावी मुद्दे हर तरफ कांग्रेस कई विरोधाभासों से घिरी है। उसकी सारी नीतियों में, सरे निर्णयों में, व्यवहार में, कथन में विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित है। लोकसभा के चुनाव उग्र से उपग्रह होते जा रहे हैं, लोकतंत्र के महायज्ञ की 7 मई को आधी से ज्यादा आहुति पूरी होने वाली है, पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान होने वाला है। इसके बाद 543 में से आधे से अधिक यानी 284 सीटों पर मतदान पूर्ण हो जाएगा। जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा की ओर रुख करते नेताओं ने कांग्रेस की नींद उड़ा कर रख दी है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आक्रामक, तीक्ष्ण एवं तीखे आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी में लगातार हो रही टूट एवं पार्टी छोड़ने के कांग्रेसी नेताओं के सिलसिले को रोक नहीं पा रही है। इस बड़े संकट से बाहर निकलने का रास्ता कांग्रेस को नहीं सूझ रहा है। कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे बड़ा झटका इंदौर में लगा, जहां से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय काठि बम ने नामांकन वापसी के अंतिम दिन मैदान ही छोड़ दिया और वो भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले विपक्षी दलों का गठबंधन ह्यूमिंडियाह को खुजाहो में झटका लगा था, जहां आपसी समझौते के चलते यह सीट समाजवादी पार्टी को दी गई थी। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा दीपक यादव का पर्चा निरस्त हो गया। इस तरह राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से दो- खुजाहो और इंदौर ऐसी है जहां से कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता महंती ने यह कहते हुए टिकट लौटा दिया कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए धन नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में ओडिशा विधानसभा चुनावों के लिए कमजोर उम्मीदवार उतारे गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में राजनीतिक अपरिपक्वता, दिशाहीनता एवं निर्णय-क्षमता का अभाव है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कांग्रेस कई राज्यों में वेमन से चुनाव लड़ रही है। आज के परिदृश्यों में कांग्रेस अनेकों विरोधाभासों एवं विसंगतियों से भरी है। चुनाव प्रचार हो या उम्मीदवारों का चयन, राजनीतिक वायदे हो या चुनावी मुद्दे हर तरफ कांग्रेस कई विरोधाभासों से घिरी है। उसकी सारी नीतियों में, सरे निर्णयों में, व्यवहार में, कथन में विरोधाभास स्पष्ट परिलक्षित है। यही कारण है कि उसकी राजनीति में सत्य खोजने से भी नहीं मिलता। उसका व्यवहार दोगला हो गया है। दोहरे मापदण्ड अपनाने से उसकी हर नीति, हर निर्णय समाधानों से ज्यादा समस्याएं पैदा कर रही हैं। यही कारण है कि कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने या फिर चुनाव लड़ने से इनकार करने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह निर्णय क्षमता का अभाव ही है या हार का डर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्रमशः अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय लेने में बड़ी कोताही बनती है। अब राहुल ने अमेठी में स्मृति ईरानी का सामना करने में स्वयं को अक्षम पाया तो रायबरेली से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और प्रियंका एक बार फिर चुनाव लड़ने से दूर ठिक गई। राहुल गांधी का अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ना भी कांग्रेस की दिशाहीनत का सूचक है। यह हास्यास्पद है कि गांधी परिवार के करीबी एवं चाटुकार कांग्रेस नेता राहुल के अमेठी से चुनाव न लड़ने के फैसले की यह कहकर बड़ी राजनीति जीत बता रहे हैं कि पार्टी ने स्मृति ईरानी का महत्व कम कर दिया। क्या सच यह नहीं कि कांग्रेस ने अमेठी से स्मृति ईरानी की जीत सुनिश्चित करने का काम किया है? राहुल गांधी का दो-दो सीटों से का चुनाव लड़ना भी यह दर्शाता है कि दोनों में से एक सीट पर तो वे जीत हासिल कर ही ले रहे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का सेक्षन 33 प्रत्याशियों को अधिकतम दो सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति भी देता है। देश में लोकतंत्र की जड़ें लगातार मजबूत हो रही हैं। ऐसे में नेताओं के एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने को लोकर विसंगतियां भी सामने आ रही हैं। विमर्श इस बात पर हो रहा है कि जब एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है तो प्रत्याशी को दो सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों होनी चाहिए? नेता अपने राजनीतिक हितों के लिए एक साथ दो सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और दोनों सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में अपनी सुविधानुसार एक सीट से इस्तीफा दे देते हैं। कानूनी रूप से उनके लिए ऐसा करना जरूरी भी है। फिर उस सीट पर उपचुनाव होता है। इसमें न सिर्फ करदाताओं का पैसा खर्च होता है बल्कि उस क्षेत्र के मतदाता भी टगा हुआ महसूस करते हैं। इस बात की पड़ताल जरूरी है कि दो सीटों से चुनाव लड़कर राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या इस व्यवस्था से सिर्फ अपने राजनीतिक हित साध रहे हैं?

बाढ़, बाढ़ बचाव व्यवस्था एवं आपदा प्रबन्धन को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक

अजमेर। जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने कहा कि मानसून के दौरान बाढ़ की सम्भावना की स्थिति में उससे बचाव तथा आपदा प्रबन्धन की समस्त तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाएं। वे सोमवार को कलेक्ट्रेट में सभावित बाढ़, बाढ़ बचाव व्यवस्था एवं आपदा प्रबन्धन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।

उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थिति में प्रारम्भिक दो घंटों को गोल्डन ऑर्वर्स कहा जाता है। इस समय तक अधिकतम बचाव कार्य आरम्भ हो जाने चाहिए। इसके लिए रेस्पोन्स समय कम करने का प्रयास किया जाए। उपर्युक्त स्तर पर भी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को प्रतिबन्धित रखें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समस्त एम्बुलेन्सों के उपकरणों एवं संसाधनों की जांच की जाए। समस्त आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहें। जल भराव के क्षेत्रों से सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपचार की समुचित पुख्ता व्यवस्था करें।

उन्होंने कहा, आनासागर के जल तल की लगातार मॉनीटारिंग की जाए क्योंकि

आवश्यकता होने पर गेट खोले जाएं। उन्होंने नगरीय एवं स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारियों, पंचायतराज से जुड़े अधिकारियों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जिले के समस्त बांधों के गेटों की ग्रीसिंग समय पर कराने, जल निकास की समस्त बाधाएं समय रहते हुए दूर करने, बांधों का कचरा साफ कराने तथा पंचायतीराज विभाग के अधीन बांधों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि फॉयसागर झील की पाल के रिसाव को रोकने के लिए मानसून से पहले ही तैयारी रखें। बांधों से सम्बन्धित कार्यों को 31 मई तक पूर्ण कर लें। समस्त बांधों के सुरक्षित होने की जांच करें। आवश्यकता नुसार मरम्मत कराएं। बाढ़ कर्ने जैसी प्लान तैयार किया जाए। मॉक ड्रिल जैसी कार्यक्रम संचालन तात्पर्य के स्थिति में भी दृष्टिगोचर होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक संसाधन एवं सामग्री की उपलब्धता का चार्ट बनाया जाए। इसमें सम्बन्धित व्यक्ति से सीधे सम्पर्क करने में आसानी रहेगी। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सुरक्षित भवनों का चिह्नीकरण करें।

निर्माण कार्य का भुगतान नहीं करने पर अदालत से पीडब्ल्यूडी ऑफिस का कुर्की आदेश लेकर आया ठेकेदार

अजमेर। पुष्कर महाविद्यालय में निर्माण कार्य का ठेका देने के बावजूद ठेकेदार मैसर्स पूजा कन्स्ट्रक्शन को उसके द्वारा किए कार्यों का भुगतान नहीं करने पर अदालत के सेल आमीन राजेश जैन अपनी टीम के साथ कुर्की आदेश को पालना करने पहुंचे तो पीडब्ल्यूडी कार्यालय में खलबली मच गई। अधिकारी अधियंता ने वित्तीय स्वीकृति के बाद भुगतान करने का भरोसा दिलाकर उक्त टीम से समय मांगा है। जिससे फिलहाल कुर्की की कार्रवाई टल गई किंतु भुगतान नहीं होने पर इस कार्रवाई को दोबारा भी किया जा सकता है। मैसर्स पूजा कन्स्ट्रक्शन के वकील सत्यकिशोर सक्सेना व आशीष सक्सेना के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसका अंतिम बिल का भुगतान और उसके द्वारा जमा कराई गारंटी राशि व अन्य जमा वापस करने में अड़चन लगाना शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि मैसर्स पूजा कन्स्ट्रक्शन ने वाणिज्यिक न्यायालय में उक्त राशि प्राप्त करने के लिए मुकदमा पेश किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर वादी मैसर्स पूजा कन्स्ट्रक्शन को पीडब्ल्यूडी से बकाया राशि 14 लाख 70 हजार 977 रुपए 30 पैसे प्राप्त करने का अधिकारी भरोसा दिलाकर वापस करने के लिए एक बड़े बोलीपेड मूल्य पर नहीं कर पाया, क्योंकि उक्त काम के लिए कलक्टर से इजाजत मिलना आवश्यक था। आवेदन



करने के बाद कई बार प्रयास करने के बावजूद कलक्टर से इजाजत नहीं मिलने पर बोलिंग का काम नहीं हुआ। जिससे पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसका अंतिम बिल का भुगतान और उसके द्वारा जमा कराई गारंटी राशि व अन्य जमा वापस करने में अड़चन लगाना शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि मैसर्स पूजा कन्स्ट्रक्शन ने वाणिज्यिक न्यायालय में उक्त राशि प्राप्त करने के लिए मुकदमा पेश किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर वादी मैसर्स पूजा कन्स्ट्रक्शन को पीडब्ल्यूडी से बकाया राशि 14 लाख 70 हजार 977 रुपए 30 पैसे प्राप्त करने का अधिकारी भरोसा दिलाकर वापस करने के लिए मुकदमा पेश किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनक

